

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)

देहरादून : दिनांक : 05 अगस्त, 2016

विषय: द्विवर्षीय डी0एल0एड0/डी0पी0एस0ई0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु निजी संस्थाओं को अनुमति प्रदान न किये के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य में अवस्थित 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय से ही प्राथमिक अध्यापकों हेतु द्विवर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिये इस हेतु एक ही व्यवस्था "द्विवर्षीय डी0एल0एल0 (Diploma-in-Elementary Education) पाठ्यक्रम" के संचालन के निर्देश दिये हैं। तत्क्रम में ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के राजकीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है।

2. विगत दो-तीन वर्षों से राज्य में अवस्थित विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा एन0सी0टी0ई0, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर को द्विवर्षीय डी0एल0एड0/डी0पी0एस0ई0 (Diploma-in-Pre-School Education) संचालित किये जाने के लिए आवेदन किये जा रहे हैं। एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर एन0सी0टी0ई0 रेग्यूलेशन, 2014 के अनुसार राज्य सरकार की अनापत्ति (NOC)/संस्तुति अर्निवार्य है।

3. निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा द्विवर्षीय डी0एल0एड0/डी0पी0एस0ई0 पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति की मांग के दृष्टिगत शासन द्वारा अधोवर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निजी संस्थानों को द्विवर्षीय डी0एल0एड0/डी0पी0एस0ई0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनापत्ति (NOC) प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया है:-

- 1) उत्तराखण्ड राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के लिये अध्यापकों की मांग के सापेक्ष राजकीय जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट्स) में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण दिये जाने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।
- 2) राज्य की 13 डायट्स में प्रति डायट 100 अर्थात् कुल 1300 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तथा वर्तमान में प्रति डायट 50 के अनुसार 650 प्रशिक्षु वर्तमान में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

- 3) राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्राविधानित शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 के विपरीत 1:23 है।
 - 4) राज्य की आवश्यकता से अधिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार के राजकीय डायट्स में उपलब्ध है।
 - 5) राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक हेतु राज्य में मांग के सापेक्ष पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में निजी संस्थानों को डी0एल0एड0/डी0पी0एस0ई0 प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति नहीं दी जा सकती है। यदि निजी संस्थानों के द्वारा इस प्रकार के पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं तो राज्य में प्रशिक्षितों की संख्या मांग से अधिक होने से विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने की सम्भावना होंगी जिससे बेरोजगार राज्य के लिए भविष्य में समस्या बनेंगे।
 - 6) इस सम्बन्ध में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्यप्रदेश एवं तेलंगाना जैसे राज्यों ने भी अपने यहां निजी संस्थानों को डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की है।
4. उक्त के अतिरिक्त इसी विषय में कुछ निजी संस्थानों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद दायर किये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के द्वारा उपरोक्तानुसार ही स्टैण्ड लिया गया है।
5. कुछ संस्थानों द्वारा DPSE (Diploma in Pre-School Education) पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति के लिये आवेदन किया जा रहा है जिसके क्रम में भी अवगत कराना है कि राज्य के राजकीय विद्यालयों में प्री-स्कूलिंग/प्री-नर्सरी की कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था नहीं है और न ही उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 तथा समय-समय पर संशोधित सेवा नियमावली में प्री-प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है।
6. अतः निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि कृपया डी0एल0एड0/डी0पी0एस0ई0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु NCTE से प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों का निस्तारण उपरोक्तानुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि — प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।
7. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, एन0सी0ई0टी0, जयपुर (राजस्थान)।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंजना)

अपर सचिव

५